भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3493
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

लिबरल आर्ट्स शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण

†3493. **थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तीव्र प्रसार ने प्रौद्योगिकी जागरूकता, नैतिकता, रचनात्मकता और आलोचनात्मक जांच को साथ लाकर एक अंतःविषय शिक्षा की दिशा में विकसित होने के लिए लिबरल आर्ट्स शिक्षा की आवश्यकता सृजित की है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत सुधारों को अभिकलनात्मक साक्षरता, एआई नैतिकता, संचार कौशल, सामाजिक विज्ञान और उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में समस्या समाधान दक्षताओं को सम्मिलित करते हुए लिबरल आर्ट्स पाठ्यक्रम के साथ संरेखित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सहायताप्राप्त विश्वविद्यालयों ने किस प्रकार डेटा साइंस, डिजिटल अध्ययन और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ मानविकी को एकीकृत करने वाले अंतःविषय लिबरल आर्ट्स कार्यक्रम शुरू किए हैं; और
(घ) क्या सरकार द्वारा कृत्रिम प्रौद्योगिकी संवर्धित कार्यस्थलों के लिए लिबरल आर्ट्स स्नातकों को तैयार करने के लिए कोई राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके अंतर्गत किन-किन विशेषताओं की परिकल्पना की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने समग्र, बहु-विषयक और छात्र केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की है। एनईपी 2020 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई समूहों में बदलने की परिकल्पना दी गई है ताकि छात्रों को कलात्मक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक विषयों सहित विभिन्न विषयों में पूर्ण रूप से सक्षम बन सकें। इसका बहु-विषयक शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों के भीतर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का भी लक्ष्य है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलने के लिए दिशानिर्देश" जारी किए हैं। दिशानिर्देशों का उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षा के लिए आवश्यक संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सिंगल स्ट्रीम संस्थानों को बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और डिग्री प्रदान करने वाली स्वायत्त एचईआई में बदलना है। जैसा कि एआईएसएचई 2023-24 में बताया गया है, 500 से अधिक विश्वविद्यालय और 5000 से अधिक संबद्ध कॉलेज बहु-विषयक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के परिचालन के लिए एसओपी" को एनसीआरएफ के कार्यान्वयन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में अधिसूचित किया है। एसओपी में लिबरल आर्ट्स के छात्रों सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए कार्यक्रम के लिए कुल क्रेडिट का 50% तक अर्जित करने की अनुमति है। जैसा कि एआईएसएचई 2023-24 में बताया गया है, 700 से अधिक विश्वविद्यालयों और 7500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों ने एनसीआरएफ को अपनाया है।

यूजीसी ने "स्वयम विनियमों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क" को भी अधिसूचित किया है। विनियमन स्वयम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सेमेस्टर में कुल पाठ्यक्रमों के 40% तक की अनुमति है। स्वयम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आईआईटी, आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 140 से अधिक निशुल्क एआई-संबंधी पाठ्यक्रम हैं। अब तक, 50 लाख से अधिक छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों में नामांकन किया है।

सरकार ने लिबरल आर्ट्स के छात्रों सहित सभी शिक्षार्थियों हेतु स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस (एसओएआर) कार्यक्रम भी शुरू किया है। एसओएआर एक संरचित कौशल विकास पहल है जिसे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत, पेशेवर और कार्यस्थल की तत्परता का निर्माण करने के लिए निर्मित किया गया है। यह क्यूरेटेड मॉड्यूल के माध्यम से महत्वपूर्ण सोच, डिजिटल साक्षरता और व्यवहार कौशल जैसी आवश्यक दक्षताओं को मजबूत करता है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को तकनीक आधारित कार्य वातावरण में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक क्षमताओं से सुसज्जित करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) कार्यान्वित है, जिसका उद्देश्य निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करके उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है। योजना में विभिन्न घटकों जैसे शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए अनुदान (जीएसयू), और कॉलेजों को मजबूत करने के लिए अनुदान (जीएससी) आदि के तहत सहायता के माध्यम से राज्य की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, साम्यता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है।

पीएम-उषा के बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) घटक के तहत, प्रत्येक 100 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए 35 विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। एमईआरयू के बीच समूह बनाने और संसाधन साझाकरण; प्रत्येक एमईआरयू के भीतर घटक कॉलेजों के बीच; और 21वीं सदी के कौशल आदि विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सहित शिक्षा में पहुंच, साम्यता और उत्कृष्टता बढ़ाने के उद्देश्य से 44 अनिवार्य गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालयों को एमईआरयू वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

****